This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार 22 जून, 2012/1 आषाढ़, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग
(नि0—III)

अधिसूचना

शिमला—2, 21 जनू, 2012

संख्या पीईआर (एपी)—सी—ए (3)—8/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 21 मई, 2011 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, निजी सहायक, (वर्ग—II, अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, निजी सहायक, (वर्ग—II, अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उपाबन्ध—"क" का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग निजी सहायक, (वर्ग—II, अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011, के उपाबन्ध—"क" में स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक / कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का संयुक्ततः ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में चार वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य होना चाहिए, दोनों के न होने पर कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका सोलह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सोलह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर :

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I:— उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II :— उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे : —

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप—मण्डल।
3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड. और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़– भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच–बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त :

परन्तु जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा से सम्बन्धित परन्तुक ऐसी सेवाओं/स्थापनों/ विभागों को लागू नहीं होंगे, जिनकी सेवाएं अस्थानान्तरणीय हैं और ऐसे क्षेत्रों में उनके पद नहीं है।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः–अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हैं या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दि हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हैं और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हैं।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा
प्रधान सचिव (कार्मिक)।

———————

[Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-8/2010 Dated: 21-06-2012 as required under clause-(3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st June, 2012

No. Per (AP)-C-A (3)-8/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Personal Assistant, (Class-II, (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification of even number dated the 21st May, 2011, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Personal Assistant, (Class-II, Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Personal Assistant, (Class-II, Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 for the existing provision against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:-

"By promotion from amongst the Senior Scale Stenographers of concerned Departments who possess 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers with 11 years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Senior Scale Stenographer/Junior Scale Stenographer out of which four years essential service as Senior Scale Stenographer, failing both by promotion from amongst the Junior Scale Stenographers possessing 16 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gus thyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad saini, Ma and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District:

Provided that the provisos regarding essential service in the tribal/difficult areas shall not be applicable to such services/ establishments/ Departments whose services are non-transferrable and do not have posts in such areas.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order,
Manisha Nanda,
Principal Secretary (Personnel).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 20 जून, 2012

संख्याः रैव0 बी. ए. (3) 5/2000–II.–हिमाचल प्रदेश टैनन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज (अमैंडमेंट) रूल्ज, 2012 के प्रारूप को, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 20 मार्च, 2012 द्वारा, हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 123 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, इनके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए ई–राजपत्र हिमाचल प्रदेश दिनांक 23 मार्च, 2012 को प्रकाशित किया गया था;

और उक्त प्रारूप नियमों की बावत जनसाधारण से कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अभिधृति एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश टैनन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टैनन्सी एण्ड लैण्ड रिफौमर्ज (संशोधन) रूल्ज, 2012 है।

2. **रूल 38–A का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश टैनन्सी एण्ड लैण्ड रिफौमर्ज रूल, 1975 के रूल 38–A में सब–रूल (3) के सैकण्ड प्रोवाइजों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"Provided further that the State Government may for reasons to be recorded in writing, extend the said period.".

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव (राजस्व)।

———————

[Authoritative English Text of this Department's Notification No.Rev.B.A. (3)- 5/2000-II, dated 20th June,2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

Revenue Department

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th June, 2012

No. Rev. B.A. (3)-5/2000-II.—Whereas the draft Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules, 2012 were published in e-Rajpatra, Himachal Pradesh on 23rd March, 2012, vide notification of even number dated the 20th March,2012 as required under the provisions of section 123 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act,1972 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby within a period of 30 days from the date of their publication:

And, whereas no objection/suggestion has been received from general public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 122 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975, namely:-

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules, 2012.

2. Amendment of rule 38-A.—In rule 38-A of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975, in sub-rule (3), for second proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided further that the State Government may for reasons to be recorded in writing, extend the said period.".

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Revenue).

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16-6-2012

No. Rev. 1-9 (Stamp)3/79/2010-II.—In exercise of the powers conferred by Sections 78 and 79 of the Registration Act,1908 (XVI of 1908), as applicable to the State of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to further add the **Article–II** to **IX** at the end of **Article–I** of the Table of Registration Fees, as notified vide Notification No. Rev. 1-9 (Stamp) 3/79/2010-II Dated 12th Jan, 2012 for whole of Himachal Pradesh to be effective from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, namely:-

<table>
<tr><td>Article-II
For inspection of any number or entries or registered documents:</td><td>Rs. 50.00 for a calendar year.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Provided that no search fee shall be charged If the search is made at the request of any Court for investigation or inquiry.</td></tr>
<tr><td>Article-III
For granting the copies of registered documents:-
(i) up to 5 sheets;
(ii) more than 5 sheets.</td><td>Rs. 10.00 for single document;
Rs. 20.00 for single document.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Explanation.- Government Officers/Officials, who want to search the register or take copies of documents for bonafide public purposes, will be exempted from the payment of the fees under Articles II and III above.</td></tr>
<tr><td>Article–IV
For discretionary registration by the Registrar of the District.</td><td>Additional fee of Rs. 50.00 for each document shall be charged.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Note.– The additional fee under this Article is not payable on the registration of Wills, Authorities to Adopt and Depositing, Withdrawing & Opening the Sealed Cover Wills.</td></tr>
<tr><td>Article–V
For the issue of commission and for attending at private residences:-
In all cases.</td><td>Rs. 50.00 for single transaction.</td></tr>
</table>

Note.– In addition to the above fee, the person on whose behalf the journeys referred to in paragraph 10 of the Registration Manual are performed shall pay to the Government such additional sum as may be necessary to cover the cost of travelling allowance of registering office: Provided that the place visited is more than one km. from the registration office.	
Article –VI For filing transactions.	Rs. 20.00.
Article-VII For the Authentication of a Power of Attorney under section 33 of Registration Act, 1908, if such Power of Attorney is executed out of the State of Himachal Pradesh.	Additional fee of Rs. 100.00 shall be charged.
Article–VIII When under section 36 of the Registration Act, 1908, application is made to issue and to serve a summon, process fee and remuneration of the person summoned, at the rates prescribed for the civil courts of the state are to be levied from the person at whose instance or on whose behalf the application is made. When, however, the person summoned is the person who has executed the document, the remuneration is not to be allowed to him.	
Article–IX For the safe custody of documents remaining unclaimed after registration is refused. When application for return of registered document or of a document the registration of which has been refused is made more than three month from the date of such registration or refusal, as the case may be.	The Custody fee of Rs 50.00 shall be charged.

By order,
DEEPAK SANAN,
Principal Secy.-Cum-FC(Revenue).

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 21.06.2012

संख्याः टी.पी.टी.–ए (3) 2/2010.–प्रारूप संशोधन नियम नामतः हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकलज़ (तृतीय संशोधन) नियम, 2012, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के उपबन्धों के अनुसरण में समसंख्यक अधिसूचना तारीख 12.06.2012 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभवित व्यक्तियों से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के अधीन यथा अपेक्षित, इनके प्रकाशन की तारीख से 07 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 13.06.2012 को प्रकाशित किए गए थे ।

2. विहित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों से सम्बन्धित जन साधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

3. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 211 के साथ पठित धारा 41(13), 65(2)(ट), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

संक्षिप्त नाम ।	1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान (तृतीय संशोधन) नियम, 2012 है ।
नियम 47—क का प्रतिस्थापन ।	2. हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के नियम 47—क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :— " 47—क देय तारीख के पश्चात यान के रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विलम्ब फीस —यदि मोटरयान का स्वामी , मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 41 की उपधारा (1) या, उपधारा (8) के अधीन, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 47 और 52 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, आवेदन करने में असफल रहता है , तो वह, केन्द्रीय मोटरयान नियम , 1989 के नियम 81 के अधीन यानों के रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त, विलम्ब फीस की निम्नलिखित रकम के संदत्त के लिए दायी होगा, अर्थात :—

देरी से रजिस्ट्रीकरण के लिए विलम्ब फीस

क्र.सं संख्या	विलम्ब की अवधि	विलम्ब फीस	
		गैर परिवहन यान	परिवहन यान
1.	तीस दिनों से अधिक किन्तु 90 दिनों से अनाधिक विलम्ब के लिए ।	500 / रूपए	1000 / रूपए
2.	90 दिनों से अधिक किन्तु 180 दिनों से अनाधिक विलम्ब के लिए ।	1000 / रूपए	2000 / रूपए
3	180 दिनों से अधिक किन्तु 360 दिनों से अनाधिक विलम्ब लिए		
4	360 दिनों से अधिक किन्तु 540 दिनों से अनाधिक विलम्ब के लिए	1500 / रूपए	3000 / रूपए
5	540 दिनों से अधिक विलम्ब के लिए ।	3000 / रूपए`	4000 / रूपए
		4000 / रूपए	5000 / रूपए

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की देरी से नवीकरण हेतु विलम्ब फीस ।

<u>मोटर साईकल के लिए (दो पहिया मोटरयान)</u>

क0स0	विलम्ब की अवधि	विलम्ब फीस (गैर परिवहन यानों के लिए)
1.	एक दिन से अधिक किन्तु 30 दिनों से अनाधिक विलम्ब के लिए ।	20/ –रूपए
2.	30 दिनों से अधिक किन्तु 90 दिनों से अनाधिक विलम्ब के लिए ।	50/– रूपए
3.	90 दिनों से अधिक किन्तु 180 दिनों से अनाधिक विलम्ब के लिए ।	100/–रूपए
4.	180 दिनों से अधिक विलम्ब के लिए ।	रू0 500/–रूपए

<u>मोटरकार के लिए (चौपहिया)</u>

क0स0	विलम्ब की अवधि	विलम्ब फीस (गैर परिवहन यानों के लिए)
1	एक दिन से अधिक किन्तु 30 दिनों से अनाधिक विलम्ब के लिए ।	100/ –रूपए
2.	30 दिनों से अधिक किन्तु 90 दिनों से अनाधिक विलम्ब के लिए ।	200/–रूपए
3.	90 दिनों से अधिक किन्तु 180 दिनों से अनाधिक विलम्ब के लिए ।	500/–रूपए
4.	180 दिनों से अधिक विलम्ब के लिए ।	रू0 2000/– रूपए ।".

आदेश द्वारा,
हस्ता0/
अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।

———————

[Authoritative English Text of this department notification NO. TPT-A(3)2/2010 , dated 20/06/2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21/06/2012

No. TPT-A(3)2/2010.—Whereas the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2012 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on dated 13/06/2012,

vide notification of even number dated 12/06/2012 in pursuance of the provision of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act NO. 59 of 1988) for inviting objections and suggestion from person(s) likely to be affected thereby, within a period of 07 days from the date of publication;

2. And , whereas no objections/ suggestions have been received from general public on the said draft rules.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 41(13), 65 (2) (k) read with sections 211 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:-

Short title	1	These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2012.
Substitution of rule 47-A.	2.	For rule 47-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:-
		"47-A. Late fee for submitting application for registration or renewal of vehicles after the due date- If the owner of a motor vehicle fails to make an application under sub-sections (1) or sub-section (8) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 , within the period specified in rules 47 and 52 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, he shall be liable to pay the following amount of late fee in addition to the fee specified for registration of vehicles or renewal of registration certificate under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

Late Fee for late Registration.

S.NO	Period of delay	Late fee	
		Non-Transport Vehicle	Transport Vehicle
1.	For delay exceeding 30 days but not exceeding 90 days.	Rs. 500/-	Rs. 1000/-
2.	For delay exceeding 90 days but not exceeding 180 days	Rs. 1000/-	Rs. 2000/-
3.	For delay exceeding 180 days but not exceeding 360 days.	Rs. 1500/-	Rs.3000/-
4.	For delay exceeding 360 days but not exceeding 540 days	Rs. 3000/-	Rs. 4000/-
5.	For delay exceeding 540 days	Rs. 4000/-	Rs. 5000/-

Late Fee for late renewal of Certificate of Registration

For motor cycle (Two wheeled motor vehicle).

S.NO	Period of delay	Late Fee (for non-transport vehicles).
1.	For delay exceeding 1 day but not exceeding 30 days	Rs. 20/-
2.	For delay exceeding 30 days but not exceeding 90 days	Rs. 50/-
3.	For delay exceeding 90 days but not exceeding 180 days	Rs. 100/-
4.	For delay exceeding 180 days	Rs. 500/-

For motor car(Four wheelers).

S.NO	Period of delay	Late Fee (for non-transport vehicles).
1.	For delay exceeding 1 day but not exceeding 30 days	Rs. 100/-
2.	For delay exceeding 30 days but not exceeding 90 days	Rs. 200/-
3.	For delay exceeding 90 days but not exceeding 180 days	Rs. 500/-
4.	For delay exceeding 180 days	Rs. 2000/- ".

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary (Transport).

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 15 जून, 2012

संख्या : विद्युत–छः (5)–55 / 2010.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मझोली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 220 के0 वी0 लाईन जमटा से देवनी व 132 के0 वी0 लाईन देवनी से 132 / 33 / 11 के0 वी0 सब–स्टेशन (जोहडो) कालाअम्ब के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला–4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला–4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघो में)
सिरमौर	नाहन	मझोली	16 / 1	0–6 बीघा
			कुल कित्ता– 1	**कुल रकवा– 0–6 बीघा**

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव (विद्युत)।

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 15 जून, 2012

संख्या : विद्युत–छः (5)–24/2012.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को भारत सरकार के व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल गधरियाणा, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में 400/220 के0 वी0 सब–स्टेशन के सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आवश्यक हैं। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता एवं उप–मण्डलाधिकारी (ना0) हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला	तहसील	मुहाल	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
हमीरपुर	हमीरपुर	गधरियाणा	1467/1	00–00–12
			1468/1	00–00–18
			1466 मिन	00–00–51
			1474 मिन	00–00–57
			कुल कित्ता– 4	**कुल रकवा– 00–01–38**

आदेश द्वारा,
हस्ता/–
प्रधान सचिव (विद्युत)।

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 15 जून, 2012

संख्या : विद्युत–छः (5)–25/2012.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को भारत सरकार के व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल चौकी कनकरी, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में 400/220 के0वी0 सब–स्टेशन के सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आवश्यक हैं। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता एवं उप–मण्डलाधिकारी (ना0) हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला	तहसील	मुहाल	खसरा नम्बर	रकबा (कनाल–मरले में)
हमीरपुर	हमीरपुर	चौकी कनकरी	1900/1/1	00–08
			1903/1	00–11
			1904/1	00–02
			3598/1905/1	00–02
			3599/1905/1	00–02
			3600/1905/1	00–02
			1907/1	00–03
			1908/1	00–03
			1909/1	00–02
			1921/1	00–06
			1924/1	00–04
			1927/1	00–05
			1930/1/1	00–01
			1930/2/1	00–06
			1930/3/1	00–01
			2011/1/1	00–02
			2011/2/1	00–02
			2024/1	00–11
			2067/1	00–03
			कुल कित्ता– 19	**कुल रकवा– 03–16**

आदेश द्वारा,
हस्ता/–
प्रधान सचिव (विद्युत)।

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 20th June, 2012

No. IPH-B (F)-4-7/2005-II.—In order to promote people's participation in the targeted areas of Ground water management, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to launch Chief Minister's Rain Water/Roof Top Water Harvesting Award in the State with an objective to encourage the registered Non-Governmental Organizations (NGOs)/Gram Panchayats/urban local Bodies/Institutions/Corporate Sector and Individuals, who have achieved excellence in the field of ground water management by adopting measures of Rain Water Harvesting, Roof Top water harvesting and artificial recharge to ground water/in promoting water use efficiency/ recycling & reuse of water/awareness creation. The procedure for this purpose to be followed is as under:-

Categories for Awards:

1. For adoption of innovative practices for ground water recharge programme through Rain Water harvesting, Roof Top water harvesting and artificial recharge through peoples participation, new techniques for rainwater harvesting, in causing awareness in all water related issues, developing /implementing best practices etc.

Eligibility Criteria:

The Award is open to all registered NGOs,Gram Panchayats and Urban Local Bodies/ Institutions/Corporate Sectors and Individuals, who have achieved excellence in the field of ground water management by adopting measures of rain water harvesting, Roof top water harvesting and artificial recharge to ground water/in promoting water use efficiency /recycling and re-use of water/awareness creation. The selected NGOs/Gram Panchayats/Urban Local Bodies/Corporate sector/Individuals/Institutions should have at least two years of field experience in ground water recharge, roof top rainwater harvesting water use efficiency, water recycling or re-use of water and in awareness creation for the same. In addition, the proposals to be considered for the Award should meet the following criteria.

- Area of operation of the person, NGO, industry, institution etc. should be largely related to ground water/roof top rainwater harvesting.

- The artificial recharge works, water use efficiencies, recycling & re-use of water and awareness creation implemented to address the issues must bring out both tangible and intangible outcomes such as increasing water availability through rain water harvesting, improvement in water quality, increase in yield and number of peoples for which awareness created.

- Initiatives in constructing Recharge structures, roof top rainwater harvesting water use efficiency, recycling & re-use of water.

- Successful implementation of the practices and its replicability.

- Community participation and awareness should be an essential element of the activity.

- The structures designed should be based on sound scientific consideration for their operation & optimal efficiency.

Evaluation Criteria for Selection

A District Level Selection Committees will scrutinise and examine the eligible applications received as per the procedure laid down and shall recommend three best applications against an award of ₹ 25,0000/- each. The application to be filled is at Annexure 'A'. The field agency will furnish a report as per Annexure 'B'. The evaluation criteria will fulfill following norms.

1. Contribution for sustainability of ground water resources and its acceptance by local community.
2. Scope of replicability and suitability of transfer to other areas.
3. Economic viability of the innovative technique/ practice including environmental advantages.
4. Contribution for sustainability of ground water resources/availability of water through roof top rain water harvesting and its acceptance by local community.
5. Development of new technology for rainwater harvesting and its use recharging to ground water.

The Zonal Level Committees of IPH Department after technical scrutiny shall recommend four best applications from the above category received from various Districts under the Zone for an award of ₹ 25000/- each. Therefore, total award fixed are 12 amounting to ₹ 3.00 lac. There will be four State Awards from amongst the applicants of zonal level for the best innovative practice of water conservation, recycling and reuse, roof top rainwater harvesting water use efficiency, ground water augmentation through rain water harvesting and artificial recharge. The State Award shall have first prize money of ₹ 1.00 lakh, 2nd prize of ₹ 75,000/- and two prizes of ₹ 50,000/- as 3rd Prize. The decision of the Chairman of the State Level Selection Committee shall be final in the matter.

Constituion of Committees: The Selection Committees at District Level/Zonal Level and State Level are hereby constituted for the selection of awards and such Committees comprising the following:-

1. District Level Selection Committee

1.	Deputy Commissioner	*Chairperson*
2.	Executive Engineer (IPH)at District Hqrs.	*Member Secretary*
3.	Block Development Officer at District Hqrs.	*Member*
4.	Assistant Engineer (IPH) at District Hqrs.	*Member*

2. Zonal Level Selection Committee:

1.	Zonal Chief Engineer (IPH)	*Chairman*
2.	Zonal Superintending Engineer	*Member Secretary*
3.	Regional Director Incharge Govt. of India, CGWB, Dharamshala	*Member*

4.	Field Executive Engineer (IPH)at Zonal level	*Member*

3. State Level Selection Committee :

1.	Pr. Secretary/Secretary	*Chairperson*
2.	Engineer-in-Chief	*Member*
3.	Chief Engineer (D&M)	*Member*
4.	Zonal Chief Engineer	*Member*
5.	Director, Govt. of India, CWC, M&A Dte. Shimla	*Member*
6.	Regional Director, Govt. of India, CGWB Dharamshala	*Member*
7.	Superintending Engineer (Works)IPH Hqrs.	*Member Secretary*

Procedure for forwarding the Application for Award :

Following procedure is to be followed for forwarding eligible applications for the Award:-

1. Eligible NGOs/Gram Panchayats/Urban Local Bodies/Institutions/Corporate Sector/Individuals will submit their application to the concerned Executive Engineers/Superintending Engineers/Chief Engineers IPH/or other offices in Zone of IPH on prescribed proforma at ***Annexure-"A".***

2. District Level Selection Committee will scrutinise and examine such applications and recommend 3 best applications to Zonal Committee against an award of ₹ 25,000/- each with specifying the category.

3. The technical scrutiny of such applications will be done by a Zonal Level Committee.

4. The Zonal Committees will forward the short listed applications with the recommendations to the State Level Selection Committee for finalization of 12 zonal level awards and 4 State level awards.

This has already been uploaded on the eGazettee of the Government.

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary (IPH).

AUGMENTATION OF GROUND WATER RESOURCES -CHIEF MINISTER'S BEST RAIN WATER HARVESTING AWARDS

For ground water management by adopting innovative measures of Rain Water Harvesting, Roof Top water harvesting and artificial recharge to ground water/in promoting water use efficiency recycling & re-use of water/awareness creation.

Guidelines

Government of Himachal Pradesh
June, 2012

AUGMENTATION OF GROUND WATER RESOURCES-CHIEF MINISTER'S BEST RAIN WATER HARVESTER AWARDS

For ground water management by adopting innovative measures of Rain Water Harvesting, Roof Top water harvesting and artificial recharge to ground water/in promoting water use efficiency/recycling & re-use of water/awareness creation.

1. Preamble

Water is an essential and vital component of our life. The fast pace of urbanization and industrialization has put a lot of stress on water sources. The dependence on ground water for these supplies is increasing alarmingly.

Ground water is viewed as a common pool resource. Hence, it is necessary that this resource is protected by promoting sustainable use through technically sound management practices. The natural recharge of ground water has been substantially reduced in many areas due to human interference. It is unable to keep pace with excessive withdrawal in many areas. Thus there is a need to augment ground water resources by sustainable interventions to facilitate more recharge. The availability of sources of water and favourable hydro-geological conditions are vital for the successful implementation of artificial schemes. The State of H.P. already has a policy in the Building Bye-laws of MC/NAC etc.

In order to promote people's participation in the targeted areas, the Chief Minister's Rain Water Harvesting Award is proposed to be launched with an objective to encourage the registered Non-Governmental Organizations (NGOs) /Gram Panchayats/ urban local Bodies/ Institutions /Corporate Sector and Individuals. The award is based on pattern being followed by Delhi Government for this purpose, the following points/procedure is proposed to be considered : citation.

2. Categories for Awards:

1. For adoption of innovative practices for ground water recharge programme through Rain Water harvesting, Roof Top water harvesting and artificial recharge through peoples participation, new techniques for rainwater harvesting, in causing awareness in all water related issues, developing/implementing best practices etc.

3. Eligibility Criteria :

The Award is open to all registered NGOs,Gram Panchayats and Urban Local Bodies/ Institutions/Corporate Sectors and Individuals, who have achieved excellence in the field of ground water management by adopting measures of rain water harvesting, Roof top water harvesting and artificial recharge to ground water/in promoting water use efficiency/recycling & re-use of water/awareness creation. The selected NGOs/Gram Panchayats/Urban Local Bodies/ corporate sector/Individuals/Institutions should have at least two years of field experience in ground water recharge, roof top rainwater harvesting water use efficiency, water recycling or re-use of water and in awareness creation for the same. In addition, the proposals to be considered for the Award should meet the following criteria.

- Area of operation of the person, NGO, industry, institution etc. should be largely related to ground water/roof top rainwater harvesting.
- The artificial recharge works, water use efficiencies, recycling & re-use of water and awareness creation implemented to address the issues must bring out both tangible and intangible outcomes such as increasing water availability through rain water harvesting, improvement in water quality, increase in yield and number of peoples for which awareness created.
- Initiatives in constructing Recharge structures, roof top rainwater harvesting water use efficiency, recycling & re-use of water.
- Successful implementation of the practices and its replicability.
- Community participation and awareness should be an essential element of the activity.
- The structures designed should be based on sound scientific consideration for their operation & optimal efficiency.

4. Evaluation Criteria for Selection

A District Level Selection Committees will scrutinise and examine the eligible applications received as per the procedure laid down and shall recommend three best applications against an award of ₹ 25,0000/- each. The application to be filled is at Annexure ‘A’. The field agency will furnish a report as per Annexure ‘B’. The evaluation criteria will fulfill following norms.

1. Contribution for sustainability of ground water resources and its acceptance by local community.
2. Scope of replicability and suitability of transfer to other areas.
3. Economic viability of the innovative technique/practice including environmental advantages.
4. Contribution for sustainability of ground water resources/availability of water through roof top rain water harvesting and its acceptance by local community.
5. Development of new technology for rainwater harvesting and its use recharging to ground water.

The Zonal Level Committees of IPH Department after technical scrutiny shall recommend four best applications from the above category received from various Districts under the Zone for an award of ₹ 25000/- each.. Therefore, total award fixed are 12 amounting to ₹ 3.00 lac. There will be four State Awards from amongst the applicants of zonal level for the best innovative practice of water conservation, recycling and reuse, roof top rainwater harvesting water use efficiency, ground water augmentation through rain water harvesting and artificial recharge. The State Award shall have first prize money of ₹ 1.00 lakh, 2nd prize of ₹ 75,000/- and two prizes of ₹ 50,000/- as 3rd Prize. The decision of the Chairman of the Committee shall be final in the matter.

5. Procedure for forwarding the Application for Award :

Following procedure is to be followed for forwarding eligible applications for the Award:-

1. Eligible NGOs/Gram Panchayats/Urban Local Bodies/Institutions/Corporate Sector/ Individuals may submit their application to the concerned Executive Engineers/Superintending Engineers/Chief Engineers IPH/or other offices in Zone of IPH on prescribed proforma at ***Annexure-"A".***

2. District Level Selection Committee will scrutinise and examine such applications and recommend 3 best applications to Zonal Committee against an award of ₹ 25,000/- each with specifying the category .

3. The technical scrutiny of such applications will be done by a Zonal Level Committee.

4. The Zonal Committees will forward the short listed applications with the recommendations to the State Level Selection Committee for finalization of 12 zonal level awards and 4 State level awards.

6. Evaluation Criteria for Selection

A selection Committee will examine the eligible applications received as per the procedure laid down for the Award and based on the evaluation criteria indicated below :-

Sr. No.	Criteria	Marks
1	Relevance and significance of the work done in recharging Ground Water during the last two years	10
2	Contribution for causing awareness in water related issues in last two years.	10
3.	Development of new technology for rain water harvesting and recharging to ground water	20
3	Impact assessment of the practice/ innovation implemented for ground water recharge and improvement in ground water availability and quality	25
4	Scope of replicability and suitability of transfer to other areas	10
5	Economic viability of the innovative technique/ practice including environmental advantages	25
Total Marks		**100**

To qualify for the Award, a minimum score of 50 marks is required. The State Level Committee after technical scrutiny, shall short list application for awards. The decision of the Chairman of the Committee shall be final in the matter.

ANNEXURE-A

Application Form for Chief Minister's Best Rain Water Harvesting Award			
1.	Name of the Individual/Institution/housing society Nominated for the Award		
2.	Category (Individual/Institutional)		
3.	Address		
	Telephone Nos.		
	Fax No.		
	E-mail		
4.	Details of Rain Water Harvesting Structures completed (Give type of structures completed, their numbers, sizes etc.)		
5.	Details of scheme		
	A	Depth of ground water level	
	B	Total catchments area (in square meters)	
		Paved /Roof top/pucca area (in square meters)	
	C	Annual runoff	
	D	Runoff used for ground water recharge and surface storage. Type of usage and values are to be given.(Give separate figures in case of both)	
6.	Year of completion of Rain Water Harvesting System.		
7.	Total expenditure incurred with type of funding (Own/ Government/sponsorship/ others, specify.		
8.	Year-wise expenditure incurred in Maintenance of Rain Water Harvesting Systems		
9.	**Details on Impact Assessment** (Rise in Water Level/Change in Water Level /increase in discharge from nearby tube well, open well/ improvement of ground water quality/ availability of water from rain water storage tank)		
10.	Any other relevant details like awareness created, creative/innovative design, layout plans and photographs.		
11.	Name, Signature, Address and Telephone Nos. of nominating person (own nominations will also be considered)		

ANNEXURE-B

Inspection Report of Sub Committee For Chief Minister's Best Rain Water Harvesting Award			
1.	Name of the Individual/Institution/housing society Nominated for the Award		
2.	Address		
3.	Contact person and Telephone No.		
4.	Category (Individual/Institutional)		
5.	Details of Rain Water Harvesting Structures completed (Type of structures, their numbers, sizes etc.)		
6.	Details of scheme		
	a)	Source of water	
	b)	Depth of ground water level	
	c)	Total catchments area (in square meter)	
	d)	Roof Top/Paved/ Pucca Area (in square meter)	
	e)	Open /Green Area (in square meter)	
	f)	Annual Runoff (Cubic meters)	
	g)	Runoff used for ground water recharge and /or surface storage	
	h)	Geological Formation and sub surface lithology	
7.	Adequacy of design		
8.	Quality of RWH structure (Very Good/Good / Satisfactory /Poor		
9.	Year of completion of Rain Water Harvesting System		
10.	Total expenditure incurred with type of funding in rupees (own /Government/ sponsorship /others)		
11.	Maintenance schedule		
12.	Year-wise expenditure incurred in Maintenance of Rain Water Harvesting Systems		
13.	Quality of maintenance (Very Good/Good / Satisfactory /Poor).		
14.	Impact and Efficacy Assessment		
	a)	Rise in Ground Water Levels	
	b)	Increase in discharge from nearby tube well, Open wells	
	c)	Improvement in ground water quality	
	d)	Availability of water from rain water storage tank and any other details	

15.	Other relevant parameters.		
	a)	Awareness created (Media attention / News clippings etc.)	
	b)	Creative/innovative design, if any	
	c)	Other water conservation measures.	
16.	Any other remarks of the inspecting team		
17.	Date of inspection.		

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित